

जरूरी खबर

जयपुर में 29 को निकाली जाएगी भगवा रैली

जयपुर। युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से 29 सितंबर को सुबह 11 बजे भगवा रैली निकाली जाएगी। यह रैली खोले के हनुमान जी से होती हुई गलता गेट, रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, सांगनेरी गेट और रामलीला मैदान तक निकाली जाएगी। इस रैली में सभी साधु-संत, जनप्रतिनिधि, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और व्यापारी शामिल होंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र कुणाल शर्मा ने भगवा रैली के पोस्टर विमोचन किया। मंच राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह ने बताया कि यह संगठन की ओर से सातवीं रैली है जिसमें हमने सरकार से निवेदन करेंगे कि हिंदू को भी अपना एक देश चाहिए, इसके लिए हमारा संकल्प मात्र हिंदू राष्ट्र है।

पन्ना मीणा की हवेली पर 9 से शुरू होगा कैफेटेरिया



जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से आमरे महल स्थित पन्ना मीणा हवेली पर कैफेटेरिया का संचालन शुरू करने की कार्ययोजना तैयार हो गई है। जाकारा के मुताबिक आगामी 9 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। आरटीडीसी प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने संचालन करने के लिए आवश्यक शर्तों के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि हाल ही में आरटीडीसी एमडी सुषमा अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक राजेश सिंह शेखावत, कार्यकारी निदेशक (वित्त) धीरज सिमोदिया ने पूरी टीम के साथ हवेली पन्ना मीणा का निरीक्षण किया था। इसके बाद कैफेटेरिया के संचालन और पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं पर काम शुरू हुआ।

सच बेधड़क
दैनिक हिन्दी अखबार

आपके दिल की बात अब आपके अखबार के माध्यम से...

अखबार में प्रकाशन के लिए खबर, विज्ञापित, कार्यक्रम की सूचना आलेख एवं अपनी मौलिक रचनाएं

news@sachbedhadak.com

पर E- Mail करें।

30 साल पुराने दावे पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा- यह सरकार की संपत्ति

पूर्व राजपरिवार का जलेब चौक पर मालिकाना हक खारिज

बेधड़क। जयपुर पूर्व राजपरिवार के जलेब चौक और उसके आसपास की संपत्ति पर मालिकाना हक जताने के दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 30 साल पहले पेश किए दावे का खारिज करते हुए जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर कोर्ट ने आदेश में कहा- यह संपत्ति कोवेनेंट (अंग्रेजी शासन के दौरान बना प्रसविदा का एक नियम) में राज्य सरकार को दी गई थी। ऐसे में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ट्रस्ट के दावे को खारिज किया जाता है।



ट्रस्ट ने निजी संपत्ति बताया

वहीं ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि कोवेनेंट में यह संपत्ति राजपरिवार की निजी संपत्ति बताई गई है। इन्हें राज्य सरकार को केवल इस्तेमाल के लिए लाइसेंस के तौर पर दिया गया था। महाराजा सवाई मानसिंह ने स्वयं ट्रस्ट का गठन 16 अप्रैल 1959 को किया था। इसके बाद महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने 30 सितंबर 1972 को जलेब चौक सहित अपनी अन्य संपत्तियां ट्रस्ट में शामिल करते हुए कानूनी रूप से ट्रस्ट डीड निष्पादित की थी। ऐसे में इस संपत्ति पर ट्रस्ट का अधिकार है।

केस चल रहा है 1994 से

1994 में ट्रस्ट ने कोर्ट में दावा पेश करके कहा था कि जलेब चौक में अस्थाई दुकानें उनकी हैं और ये लाइसेंस पर दे रखी हैं। इनका लाइसेंस शुल्क ट्रस्ट में जमा होता है। निगम ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की है। ऐसे में निगम को स्थाई रूप से पाबंद किया जाए कि वह ट्रस्ट की संपत्तियों में दखल ना दे। इसी मामले पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कोवेनेंट का जिक्र कर दावा खारिज करने को कहा

नगर निगम की ओर से पेश करते हुए अधिवक्ता मुकेश जोशी ने दलील देते हुए कहा- साल 1949 में भारत सरकार और महाराजा सवाई मानसिंह के बीच कोवेनेंट निष्पादित हुआ था। उसमें साफ-साफ लिखा है कि जलेब चौक सहित टाउन हॉल और राजेंद्र हजारी गार्ड बिल्डिंग राज्य सरकार को यूज करने के लिए हैंडओवर की जाती है। वहीं, इसकी देखरेख का जिम्मा भी राज्य सरकार के पास ही रहेगा। कोवेनेंट में कहीं भी संपत्तियों को पुनः लौटाने या किसी और को हस्तान्तरण करने का जिक्र नहीं है। वहीं इस कोवेनेंट को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

निगम कार्रवाई के खिलाफ पेश किया था दावा

ट्रस्ट ने 29 जून 1994 को निगम कार्रवाई के खिलाफ दावा पेश किया था। कहा गया कि जलेब चौक और आसपास के भवन ट्रस्ट की संपत्ति हैं। जलेब चौक की खाली जमीन पर ट्रस्ट द्वारा लाइसेंसी थड़ी-ठेले और अस्थाई दुकानें चल रही हैं। निगम ने इन्हें गलत तरीके से हटाया है। निगम को ट्रस्ट की संपत्ति में दखल देने का अधिकार नहीं है। दावे पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 अदालत ने 24 जुलाई 2018 को ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ निगम ने डीजे कोर्ट में अपील की। एडीजे-2 कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को रद्द करते हुए फिर से सुनवाई के आदेश दिए। दावे पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर कोर्ट ने दावे को खारिज कर दिया

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ली बैठक, बोले...

अधिकारियों ने गड़बड़ी की, इसलिए फिर से मेयर को 3 दिन का नोटिस

सचिवालय पहुंची मुनेश की फाइल... मेयर रहेंगी या नहीं, फैसला 21 को

बेधड़क। किशनगढ़

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से फिर से मेयर को 3 दिन का नोटिस दिया है। इस मामले पर तो मैं बाद में ही अब ज्यादा कुछ कह पाऊंगा। ऐसे में अब 21 सितंबर के दिन मेयर मुनेश गुर्जर के भविष्य को लेकर कोई फैसला हो सकेगा। स्वायत्त शासन मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर मेयर मामले में चर्चा कर रहे थे। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत दी थी, वहीं अब सरकार मुनेश गुर्जर को पद से निलंबित करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को बैठक ली।



मंत्री कार्यवाहक मेयर के नाम पर पार्षदों से करेंगे चर्चा

मंत्री ने कहा कि मुनेश गुर्जर पर जो भी फैसला होगा। इसके बाद ही कार्यवाहक मेयर को लेकर पार्षदों से चर्चा की जाएगी। जो भी पार्षद राजनीति की समझ रखता होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता होगी, उसे पैमाना मानकर ही कार्यवाहक मेयर चुना जाएगा। मंत्री ने कहा कि वर्तमान मेयर के खिलाफ हमारे पास कांग्रेसी पार्षद भी आए हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी मेयर ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में कार्यवाहक मेयर बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

ये हैं आरोप

मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की पट्टे बनाने की एवज में 41 लाख रुपए की रिश्तत मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उन पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए दो दलालों के जरिए रिश्तत मांगी गई थी। सुशील के साथ दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया था। उस वक्त एसीबी ने मेयर के घर से तलाशी ली तो पट्टे की फाइलें मिली थीं। साथ ही 41 लाख रुपए नकद मिले थे। वहीं नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे। तब से ही एसीबी की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

आज होनी है हाईकोर्ट की सुनवाई

दरअसल, मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने को रिपोर्ट पर लेते हुए दो सप्ताह बाद सुनवाई होनी है। जस्टिस एनएस ढुंगर ने यह निर्देश सुभांशु सिंह ढिल्लन की याचिका पर दिया था। इसके बाद डीएलबी ने एक्शन लेते हुए 11 सितंबर बुधवार को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में डीएलबी ने मुनेश पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब मांगते हुए तीन दिन का समय दिया था। लेकिन, इस नोटिस पर मेयर ने जवाब नहीं देते हुए कोर्ट में सरकार की कार्यवाही के खिलाफ मंगलवार शाम को याचिका दायर कर दी है। ऐसे में अब सरकार को गुरुवार सुबह 10 बजे से पहले मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ फैसला कर कोर्ट में जवाब देना होगा। इसके बाद 12 सितंबर गुरुवार को एसीबी ने भी नोटिस जारी किया। इसमें लिखा- इसमें लिखा- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आपके खिलाफ अभियोजन स्वीकृत मिली है। हाईकोर्ट ने भी आपके खिलाफ दो सप्ताह (19 सितंबर तक) में चालान पेश करने के आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको 19 सितंबर सुबह 10 बजे न्यायालय में पहुंचने के लिए पाबंद किया जाता है।

युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, आरोप...

पुलिस के दम पर युवाओं की आवाज दबा रही सरकार



बेधड़क। अलवर

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक बयानों से गुस्सा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में बैरिकेडिंग पर चढ़कर मुख्य मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। इस पर पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई।

अभिमन्यु पूनिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी से भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। सरकार पुलिस के दम पर युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पूर्व

16 सूत्रीय मांगों को लेकर किया कर्मचारियों ने प्रदर्शन विद्युत भवन पर 'हल्ला-बोल'

बेधड़क। चूरु

जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर विद्युत भवन पर हल्ला बोल धरना दिया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी जयपुर पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मिकों के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चने डाली जा रही है, उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति है। प्रदर्शन में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जोपीएफ कटौती शुरू करने, एक



निगम से दूसरे निगम में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण करने, नए केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल कर्मचारियों के 2400 और 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भीति लागू करने सहित 16 सूत्री मांगें रखी। धरना प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में 13 सदस्य शामिल हुए, जबकि निगम प्रशासन की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक मौजूद रहे। वार्ता उनके चैबर में हुई।

नगर निगम ग्रेटर ने मानसरोवर में स्थापित की वाटिका नव दुर्गा की तर्ज पर लगाए नौ औषधीय पौधे



बेधड़क। अलवर

नगर निगम ग्रेटर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत बुधवार को अमृता नवाचार किया गया। इस नवाचार के तहत वार्ड नं. 76 मानसरोवर स्थित गुरु गोलवलकर पार्क में नवदुर्गा वाटिका स्थापित की गई। इस नवदुर्गा वाटिका में नव

दुर्गा की तर्ज पर नौ औषधीय पौधे लगाए गए हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पौधे लगाकर इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही वहां लगे नौ दुर्गा के चित्रों की पूजा आरती भी की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अशोक शर्मा ने मंत्री को औषधीय पौधों की जानकारी

किस देवी के नाम पर कौनसा पौधा लगाया

- नवदुर्गा में प्रथम मां दुर्गा शैलपुत्री के नाम पर हरेडू का पौधा लगाया गया।
- द्वितीय मां दुर्गा ब्रह्मचारिणी के नाम पर ब्राह्मी के पौधा लगाया गया है।
- तृतीय मां दुर्गा चंद्रघटा के नाम पर चासूर के पौधा लगाया गया है।
- चौथा मां दुर्गा कुम्भांडा के नाम पर पेठा के पौधा लगाया गया है।
- पांचवां मां दुर्गा स्कंदमाता के नाम पर अलसी के पौधा लगाया गया है।
- छठा मां दुर्गा कात्यायिनी के नाम पर मोड़या के पौधा लगाया गया है।
- सातवां मां दुर्गा कालरात्रि के नाम पर नागदीन के पौधा लगाया गया है।
- आठवां मां दुर्गा महागौरी के नाम पर तुलसी के पौधा लगाया गया है।
- नवां मां दुर्गा सिद्धिदात्री के नाम पर शतावरी के पौधा लगाया गया है।

दी। महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने बताया कि नवदुर्गा में नवदुर्गा की प्रतिमयें भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर समितियों के चैयरमैन एवं पार्षद राखी राठौड़, प्रवीण यादव, रमेश चन्द्र सैनी, अरुण वर्मा, शक्ति वाटिका में नवदुर्गा की प्रतिमयें भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर समितियों के चैयरमैन एवं पार्षद

स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा: शहर को स्वच्छता में अग्रणी बनाने पर प्रबुद्धजन के साथ चर्चा

स्वच्छता रैंकिंग के लिए निगम समन्वय और श्रमदान को देगा प्राथमिकता

बेधड़क। जयपुर

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत हेरिटेज निगम की ओर से बुधवार को शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिविल लाइन जोन में 'स्वच्छता ही सेवा 2024' के अंतर्गत बुधवार को महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई। इस सभा को अध्यक्षता सिविल लाइन जोन के उपायुक्त राकेश शर्मा जी ने की। सभा में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, और शहर को स्वच्छता में कैसे अग्रणी बनाया जा सकता है, इस पर व्यापक चर्चा हुई। उपायुक्त राकेश शर्मा ने डोर टू डोर जागरूकता अभियान, सार्वजनिक परिवहन, रिड्यू, रीयूज, रीसायकल, स्ट्रीट वेंडर जोन, और सभी कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला।



पौधारोपण और श्रमदान की आवश्यकता पर बल

उन्होंने पौधारोपण, श्रमदान और स्कूलों में सूचना, शिक्षा, और संचार गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। सभा में यह भी चर्चा की गई कि जयपुर को स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम के सभी स्तरों पर समन्वय और श्रमदान को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर वार्ड नंबर 37 के पार्षद रवि सैनी, वार्ड नंबर 38 के पार्षद हेमेट्र शर्मा, वार्ड नंबर 34 के पार्षद सुभाष व्यास, वार्ड नंबर 36 की पार्षद मंजू शर्मा और वार्ड नंबर 54 की पार्षद अंशु शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जोन उपायुक्त के निजी सहायक सुरेंद्र कुमार ओला, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

रैली निकाल आमजन को किया जागरूक

जयपुर। हवामहल जोन क्षेत्र में जनता बाजार सब्जी मंडी में गंदगी के ब्लैक स्पॉट हटाए गए, वहीं निगमकर्मियों ने बापू बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। हवामहल जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बुधवार को जनता बाजार सब्जी मंडी में सफाई अभियान चलाया गया। जिसमें आमजन को सफाई के प्रति जागरूक किया। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। वहीं कई सालों से हो रहे गंदगी के ब्लैक स्पॉट को भी सफाई कर साफ कराया। इस दौरान निगम कर्मियों के साथ व्यापारी वर्ग ने भी झाड़ू लगाई। वहीं आमजन को गंदगी और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शायत भी दिलाई। ब्लैक स्पॉट को साफ करने के बाद रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं, किशनपोल जोन में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बापू बाजार में निगम कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान बापू बाजार व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी रैली में शामिल हुए।



जरूरी खबर

तिरंगा रैली से लोगों में जगाए राष्ट्रभक्ति के भाव



चाकसू कस्तूरी देवी महाविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से चाकसू में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संघ के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख श्रीकांत भाई रहे। विधायक रामावतार बैरवा लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रांत कुटुम्ब प्रबोधन कार्यक्रम के सह संयोजक राजीव चौहान, जिला कार्यवाह महेश शर्मा, प्रांत प्रचार प्रमुख श्याम शर्मा, समाजसेवी नंदकिशोर शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

गाड़ी ने 8 साल की मासूम को मारी टक्कर, हुई मौत

बाड़मेर। जिले में बुधवार को तेज रफतार बोलोरो केपर गाड़ी ने स्कूल से लौट रही एक 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी चपेट में लेकर जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिले के चौहटन थाना इलाके के पराडिया गांव की सरहद में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां तेज रफतार बोलोरो केपर गाड़ी ने स्कूल से लौट रही 8 वर्षीय छात्रा जासमीन को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और गंभीर रूप से घायल मासूम बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया।

आसाराम की अपील से जस्टिस भाटी हुए अलग



जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुणेन्द्र सिंह भाटी ने आसाराम की अपील पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्होंने अन्य बैंच के समक्ष मामला रफर कर दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. भाटी ने आसाराम के मामले पर सुनवाई के लिए अपने आप का अलग कर दिया। दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से सजा के खिलाफ वर्ष 2018 में अपील पेश की थी। वर्ष 2018 में यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की आसाराम को सजा हुई थी और हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई। पिछले दिनों आसाराम को हाईकोर्ट ने 12 दिन की आकस्मिक पैरोल दी थी।

राज खसरा गिरदावरी एप में तकनीकी खामी से गिरदावरी में आ रही परेशानी के चलते लिया फैसला पटवारी आज से करेंगे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार

बेधड़क। अजमेर

हाल ही में सरकार की ओर से शुरू किए गए राज खसरा गिरदावरी एप में आ रही तकनीकी और व्यवहारिक समस्याएं दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के पटवारी गत 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं। अब बुधवार से राजस्थान पटवार संघ ने एप ठीक नहीं होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इसके चलते तहसीलों में काम प्रभावित हो रहा है।



पटवार संघ के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी कहना है कि समस्या के समाधान को लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवाया गया। गत

22 अगस्त को हुई बैठक में अतिरिक्त सेटलमेंट कमिश्नर की ओर से समस्याओं को वाजिब मानकर उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन

आज तक समाधान नहीं हुआ। इस पर पटवार संघ ने गत 9 सितंबर से प्रदेश में गिरदावरी के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था।

25 दिन से एप में समस्या बरकरार

चौधरी ने बताया कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी एप में समस्या वैसी की वैसी ही है। उन्होंने बताया कि विरोधस्वरूप बीते 2 दिन समस्त तहसीलों में पटवारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था। अब यह आंदोलन एप ठीक होने तक अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।

पहले वाला राजस्व अधिकारी एप था बेहतर

संघ के महामंत्री हिमंत सिंह रावत ने बताया कि 2022 तक राजस्व अधिकारी एप के जरिए गिरदावरी कार्य किया जा रहा था। इस एप के जरिए कभी कोई समस्या पटवारी को नहीं आई, लेकिन 2023 से खरीफ की फसल से राज खसरा गिरदावरी एप राज्य सरकार लेकर आई। इसमें गिरदावरी करना काफी मुश्किल हो गया है। एप खुलने में समय लेता है। एप में इंटेक्स खुलता है, जिसके आगे कोई डिटेल भी नहीं है। एप में कुआं, रास्ता या गैर मुमकिन खसरा की जानकारी नहीं है। ऐसे में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है।

पटवारियों को एप पर यह आ रही है समस्या

चौधरी ने बताया कि राज खसरा गिरदावरी एप खसरे पर खड़े होने के बावजूद एप बताता है कि लोकेशन ली जा रही है। एक एक खसरे की गिरदावरी करने में एक एक घण्टे का समय लग रहा है। राजस्थान पटवार संघ की मांग है कि बफर जोन 50 मीटर से बढ़ाकर 350 मीटर किया जाए।

धौलपुर में सुबह 4 बजे से बरसात से दौर रहा जारी

मौसम ने फिर मारी पलटी, धौलपुर में कई कॉलोनियां हुई जलमग्न

बेधड़क। धौलपुर

प्रदेश में तीन दिन बाद बुधवार से मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम जो अब आगे बढ़कर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, उसके असर से राजस्थान के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार नए सिस्टम से दो दिन तक बारिश हो सकेगी। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हुई। धौलपुर में बीते दो दिन से हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई कॉलोनियां डूब गई हैं। लोगों की शिकायत है कि पानी की निकासी नहीं होने के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मंगलवार और बुधवार को धौलपुर जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद मंगलवार को हुई बारिश शाम को थम गई। बुधवार सुबह 4 बजे से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है जो लगातार जारी है। मंगलवार को जिले में 44 एमएम बारिश दर्ज की गई थी।



प्रदेश में 59 फीसदी अधिक बारिश

राजस्थानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों में मंगलवार को दिनभर आसमान साफ रहा। प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक करीब 59 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार सितंबर के अंत तक बारिश का दौर रुक-रुककर जारी रह सकता है।

अलसुबह से हुई बारिश में सड़कें बनी दरिया

बीते दिनों हुई बारिश के बाद जिला प्रशासन ने बारिश के बाद हालात सामान्य करने की लिए एडी चोटी तक का जोर लगा दिया। जिसके बाद भी जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें कि शहर की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रही हैं। जिसमें लोगों के घर गिरने के कगार पर हैं।

पीडब्ल्यूडी के पैचवर्क पर उठे सवालिया निशान

पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जिला कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर शहर कि सड़कों पर हुई गड़कों को भरवाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पैचवर्क कराया था। महज दो दिन में ही सड़क पर कराया गया पैचवर्क पूरी तरह से उखड़ गया है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए गए पैचवर्क पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शिवनगर कॉलोनी के लोगों ने नगरपरिषद के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने नगरपरिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है नगरपरिषद की तरफ से शहर की साफ सफाई भी मानसून से पहले नहीं करवाई गई। जिस बजसे जलभराव की स्थिति बन जाती है। सड़कों पे गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं।

बुधवार सुबह से हुई झमाझम बारिश के बाद शहर की 40 से अधिक कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। साथ ही सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। शहर की

बाड़ी रोड और सैपऊ रोड की आदर्श नगर कॉलोनी, राम कुंज कॉलोनी, शिव नगर पोखरा और मानसरोवर कॉलोनी सहित एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां दो

माह से जल भराव की समस्या से जूझ रही हैं। जल भराव का सबसे ज्यादा असर मानसरोवर और शिवनगर पोखरा कॉलोनी में देखने को मिला है। बाड़ी रोड और

सैपऊ रोड पर बसी कॉलोनियों का पानी मानसरोवर और शिव नगर पोखरा होकर निकलता है, लेकिन शिवनगर पोखरा में पानी भराव की स्थिति बनी हुई है।

जिले में निवेश बढ़ाने के लिए होंगे एमओयू

23 अक्टूबर को सीकर में होगी एक दिवसीय इन्वेस्टर मीट

बेधड़क। सीकर

राजिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 23 अक्टूबर को सीकर में जिला स्तर पर भी एक दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय इन्वेस्टर मीट में जिले के प्रस्तावित निवेशकों के साथ एमओयू साइन किए जाएंगे। इस दौरान जिले के प्रमुख उद्यमों एवं एमएसएमई द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए बुधवार



को जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि शंखावाटी बड़े-बड़े उद्योगपतियों की धरती है, यहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक पर्यटन, खेल

सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने विभाग से संबंधित हितधारकों के साथ निवेश के एमओयू साइन करने के लिए निर्देशित किया।

घायल महिला को गंभीर हालत में करना पड़ा झुंझुनूं रेफर

हिस्ट्रीशीटर ने घर में महिला को मारी गोली

बेधड़क। झुंझुनूं

हिस्ट्रीशीटर ने घर में काम कर रही महिला को गोली मार दी। घटना के बाद गोली लगने से घायल महिला को सिंधाना के राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया गया। घटना सिंधाना थाना क्षेत्र के खानपुर में बुधवार शाम की। थानाधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। घायल महिला के जेट देशराज ने बताया कि शाम करीब 6 बजे वह पशुओं को चारा डाल रहा था। वहीं उसके छोटे भाई वेदप्रकाश



की पत्नी सजना (45) घरेलू काम कर रही थी। इस दौरान थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपने एक साथी के साथ उनके घर आया। उसने घर में घुसकर सजना को गोली मारी और बाजार की फसल के रास्ते फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर

जब उसने घर में जाकर देखा, तो सजना लहलुहान पड़ी हुई थी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सजना को सिंधाना के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया।

डॉ. लोकेश ने बताया कि महिला को सामने से सीने के नीचे गोली मारी गई थी। कमर में भी निशान बना हुआ है। हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर थानाधिकारी कैलाश चंद यादव मय जाबते के मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। थानाधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि आरोपी की सरगामी से तलाश की जा रही है तथा उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि आरोपी और पीड़ित परिवार में पुरानी रंजिश थी। इसी के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

शाहपुरा में बाजार बंद, स्कूलों में छुट्टी

गणपति विसर्जन के बाद पांडाल में मिले जानवर के अंग, लोगों ने दिया धरना

बेधड़क। भीलवाड़ा

शाहपुरा जिले के मुख्य बाजार स्थित चमुना बावड़ी में गणपति विसर्जन के बाद बुधवार सुबह पांडाल में जानवर के अंग मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाजार बंद करवाकर लोग धरने पर बैठ गए। मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। माहौल गरमाता देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उधर, हंगामे की सूचना के बाद शहर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुबह करीब 10 बजे छुट्टी कर दी गई। देर शाम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को अर्न्त चतुर्दशी पर धूमधाम से



गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया गया था। चमुना बावड़ी में लगे पांडाल को नहीं हटाया गया था। बुधवार सुबह लोग पांडाल में

पहुंचे। मौके पर जानवर के अंग मिले। सूचना पर पुलिस और नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी

एक महिला को किया गिरफ्तार

शाहपुरा एडिशनल एसपी चंचल ने बताया- मामले को लेकर सीसीटीवी खंगाले। इसके बाद एक महिला रश्मा बानू (60) पत्नी जहांगीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझाया

मांग को लेकर नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, गणेश उत्सव समिति के निखिल जीनगर, जयंत जीनगर समेत बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। मौके पर डीएसपी रमेश चंद्र तिवारी, शाहपुरा एसएचओ राजकुमार, एसआई प्रभाती लाल समेत कई अधिकारी डटे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। डीएसटी टीम को बुलाया गया शाहपुरा थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि डीएसटी टीम को बुला लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। अवशेष हटा दिए गए हैं। स्थिति अब शांत है।

विधायक ने किया समझाने का प्रयास

बुधवार सुबह करीब 11 बजे विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन लोग इसके लिए राजी नहीं हुए। देरी-पट्टी बिछाकर सड़क पर बैठ गए। उसके बाद बोले- हमारा विधायक कैसा हो, गोपीचंद मीणा (जहाजपुर) जैसा। विधायक लालाराम बैरवा इस समय जम्मू के अखनूर में हैं। उन्हें अखनूर में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं फुलिया (शाहपुरा) एसडीएम राजकेश मीणा धरनास्थल पर पहुंचे।

चार किलोमीटर तक निकाली आक्रोश रैली

नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी ने बताया कि गणपति पांडाल में जानवर के अंग मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शाहपुरा के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के लोग चमुना बावड़ी पांडाल में हिंदू संगठनों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए हैं। धरने पर बैठने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद आक्रोश रैली निकाली निकाली गई। रैली करीब आधा किलोमीटर लंबी थी। रैली ने करीब चार किलोमीटर की दूरी तय की। चमुना बावड़ी से शुरू होकर रैली सदर बाजार, बालाजी की छतरी, कलीजरी गेट, उदय गान्धी गेट और कुंड गेट होते हुए वापस चमुना बावड़ी स्थित धरना स्थल पर पहुंची। रैली के दौरान लोग बाजार की दुकानें बंद कराते चल रहे थे। इसके बाद फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं।

राष्ट्रपति ने प्रदान विद्यार्थियों को डिग्री, डिग्री पाकर खिले चेहरे



जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को एमएनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का लोकार्पण भी किया।

Yuva स्टोरीज

विवि के गणित विभाग में स्मार्ट क्लासरूम शुरू



बेधड़क | जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय के गणित विभाग में मंगलवार को अत्याधुनिक तकनीकयुक्त स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गयी। गणित विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी जैन ने बताया कि यह स्मार्ट क्लासरूम एक इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल पॉडियम, हाई-स्पीड इंटरनेट और अन्य उपकरणों से सुसज्जित है, जो छात्रों को एक आकर्षक और सहयोगात्मक सीखने का अनुभव प्रदान करेगा। इस स्मार्ट क्लासरूम स्थापना रणनीति की कम्पनी पीएआर टेक्नोलॉजी के इंडिया हेड रितेश के द्वारा कम्पनी के सीआरएस प्रयासों के अंतर्गत की गयी है। गणित विभाग का यूएसए डेलिगेशन द्वारा अवलोकन किया गया।

कार्यक्रम में पीएआर टेक्नोलॉजी की नेतृत्व टीम के प्रमुख सदस्य, जिनमें स्टीवन (सीटीओ), पॉल (चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर), जियो (वीपी प्रोडक्ट), रितेश (वीपी इंजीनियरिंग और हेड इंडिया), हितेश एवं पराम उपस्थित रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने स्मार्ट क्लासरूम स्थापना में PAR टेक्नोलॉजी के CSR प्रयासों की सराहना की। प्रो. कटेजा ने कहा कि इस तरह की प्रगति छात्रों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर डिजिटल युग में। गणित विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी जैन ने कुलपति की सराहना करते हुए कहा कि उनका समर्पण विश्वविद्यालय के प्रति दर्शाया।

शिक्षा विभाग ने नहीं दी टेबलेट और इंटरनेट की सुविधा कृषि संकाय के विद्यार्थियों से हो रहा दोगला व्यवहार!

बेधड़क | जयपुर

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन यहाँ पर कृषि संकाय के विद्यार्थियों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में कृषि संकाय में मेरिट (निर्धारित प्रतिशत) में आने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट नहीं मिलेंगे। कृषि से जुड़े विद्यार्थियों को तकनीक से दूर रखने के साथ नवाचार व सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में योजना से कृषि संकाय की प्रतिभाएं वंचित होंगी। राज्य में आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा में मेरिट में आने वाले 55 हजार 800 विद्यार्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य सरकार टेबलेट वितरण के साथ 3 साल तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2022 एवं 2023 में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों जिलावार टेबलेट व सिम का वितरण किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि दोनों ही वर्षों में कृषि संकाय का एक भी विद्यार्थी शामिल नहीं है। प्रो. टेबलेट योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 व 22-23 के बोर्ड की सभी कक्षाओं आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं के कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्यय के छात्र-छात्रा शामिल हैं।



राज्य मेरिट कट ऑफ परीक्षा 2022 (टेबलेट)

कक्षा	चयनित मेरिट	कट ऑफ
आठवीं	6000	90.83
दसवीं	5880	86.17
प्रवेशिका	120	75.67
बारहवीं कला	2864	90.2
बारहवीं कॉमर्स	423	83
बारहवीं साइंस	2593	85.4
वरिष्ठ उपा.	120	83.8

राज्य मेरिट कट ऑफ परीक्षा 2023 (टेबलेट)

कक्षा	चयनित मेरिट	कट ऑफ
आठवीं	6000	90.50
दसवीं	5880	87
प्रवेशिका	120	79
बारहवीं कला	2864	90.20
बारहवीं कॉमर्स	423	82.4
बारहवीं साइंस	2593	85.6
वरिष्ठ उपा.	120	79

पहले विज्ञान संकाय में शामिल, 2020 में किया था अलग घोषित

राज्य भर में 398 स्कूलों में कृषि संकाय संचालित है। पहले यह विज्ञान संकाय के साथ ही माना जाता था। लेकिन पूर्व की अशोक गहलोत सरकार द्वारा कृषि को महत्व देने की योजना को लागू करते हुए इसे अलग से कृषि संकाय 2020 में घोषित किया गया, जिससे कि प्रदेश के बच्चों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इस वर्ष भी कृषि संकाय में सैकड़ों विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

इनका कहना है...

इस मामले में शिक्षक संघ रजिस्टार के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने कहा कि राज्य के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के साथ दोगला व्यवहार सही नहीं है। कृषि विषय को अलग संकाय किया गया है। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से संघ की मांग है कि जल्द ही कृषि संकाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट दिए जाए।

आमुखीकरण शिविर में सहकारिता राज्य मंत्री बोले... नवाचारों को अपनायें और आमजन के प्रति संवेदनशील रहें : दक



बेधड़क | जयपुर

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिये सभी एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करें, जिससे कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुये अधिक से अधिक नवाचारों को अपनायें तथा आमजन के साथ संवेदनशील होकर काम करें। दक ने बुधवार को सहकारिता विभाग में नवनि्युक्त 29 सहायक रजिस्टार एवं 40 सहकारिता निरीक्षकों के आमुखीकरण के लिये अपेक्स बैंक के सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि सहकारिता में

फील्ड में पारदर्शी और खुलेमन से कार्य करें

उन्होंने नवनि्युक्त सहायक रजिस्टार एवं निरीक्षकों से कहा कि आप फील्ड में पारदर्शी एवं खुलेमन के साथ कार्य करें ताकि लोगों की सहकारिता में विश्वसनीयता बढ़े। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता का मूल मंत्र "एक सबके लिये, सब एक के लिये" में विकास की कमी खत्म न होने वाली उर्जा विद्यमान है। इसलिये हमें सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

विकास की अकूत संभावनायें हैं और हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति सहकारिता से वंचित नहीं रहे।

सहकारिता की मूल भावना का ध्यान रखें शासन सचिव एवं रजिस्टार, सहकारिता मंत्री राजपाल ने कहा कि सहकारिता की मूल भावना को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि वंचित लोगों को योजनाओं को सही समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सहकारिता मूलतः कृषक, कृषि और कृषक कल्याण से संबन्धित है।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

आमुखीकरण समारोह में विशिष्ट सहायक, सहकारिता मंत्री एस. एस. नेगी, संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक संजय पाठक, तकनीकी सहायक, रजिस्टार कार्तिकेय मिश्र, विशिष्ट अधिकारी, सहकारिता मंत्री पंकज भानु सिंह, महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक संदीप खण्डेलवाल सहित सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस जागरूकता सप्ताह शुभारंभ



बेधड़क | जयपुर

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एंड कंट्रोलर डॉ. दीपक माहेश्वरी ने चौथे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। जिसका विषय "रोगी सुरक्षा के लिए एडीआर संस्कृति का निर्माण" था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एंड कंट्रोलर ने जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य देख भाल चिकित्सकों को रोगी के स्वास्थ्य और उपचार

की बेहदरी के लिए एडीआर की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर की समन्वयक डॉक्टर मोनिका जैन ने उपस्थित सभी चिकित्सक शिक्षक, रजिस्टर्ड डॉक्टर, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, नर्सिंग विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई की। उप समन्वयक डॉ. रूपा कगाड़िया ने कहा कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को सफल बनाने में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका का उल्लेख किया।

आधुनिक युग में शास्त्रों का प्रयोग और विनियोग होना अत्यावश्यक है प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

जयपुर। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर में भारतीय विधिशास्त्र विद्याशाखा द्वारा पाठ्य-अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शास्त्रों का संरक्षण,

प्रयोग और विनियोग होना चाहिए। विभिन्न शास्त्रों के संवाद द्वारा नए शास्त्रों का निर्माण होता है। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के निदेशक प्रो. सुदेश कुमार शर्मा ने बताया देश की प्रजा ही मालिक है और परिवर्तन होना प्रकृति है इसको समझना और पाठ्यक्रम

में लागू करना यह अत्यंत ही आवश्यक है। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र पूर्वविभागाध्यक्ष प्रो. बृजकिशोर स्वामी ने धर्मशास्त्र के अध्ययन के साथ विधिशास्त्र के अध्ययन को सराहनीय कदम बताया एवं कहा कि विधि एवं विधिशास्त्र में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना

चाहिए क्योंकि विधि शास्त्र जन सामान्य के लिए है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अर्कनाथ चौधरी ने अपने व्याख्यान में विधि की उपादेयता के लिए नए व पुराने सुविचारों का देशकाल स्थिति के अनुसार ग्रहण किया जाना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाला।

सेमिनार एसकेआईटी में शुभारंभ 2024 का ओरिएंटेशन कार्यक्रम

भविष्य के प्रबंधकों को सशक्त बनाने का आह्वान

बेधड़क | जयपुर

स्वामी केशवनंद प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं ग्रामोत्थान संस्थान (एस.के.आई.टी) के प्रबंधन अध्ययन विभाग की ओर से "शुभारंभ 2024" नामक परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय "भविष्य के प्रबंधकों को सशक्त बनाना" था, जिसका उद्देश्य नवप्रवेशित एमबीए (2024-2026) के छात्रों को प्रबंधन क्षेत्र में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ जे.सी. बोस सेमिनार हॉल, एस.के. आई.टी. में हुआ। इसकी शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन



के साथ की गई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रो. डॉ. एस.एल. सुराणा (निदेशक अकादमिक, एसकेआईटी), प्रो. आर.के. जैन (डीन, एसकेआईटी),

मुख्य अतिथि डॉ. राजेश मेथी, सम्माननीय अतिथि प्रिंस कुमार और विशिष्ट अतिथि सचिन खंडेलवाल का हार्दिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

डॉ. राजेश मेथी (चेयरपर्सन, आईएसटीडी, जयपुर) ने अपने प्रेरणादायक भाषण के माध्यम से छात्रों को भविष्य के प्रबंधकों के रूप में तैयार होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने

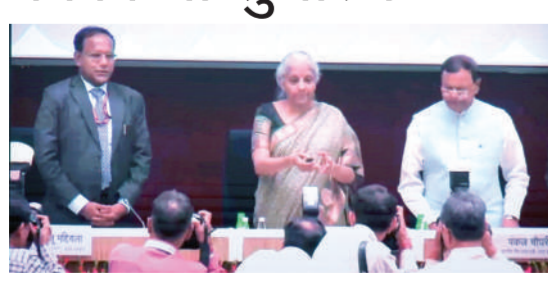
प्रबंधन के विभिन्न आयामों और आवश्यक कौशलों पर विशेष जोर दिया। विशिष्ट अतिथियों में प्रिंस कुमार (राजस्थान प्रमुख, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) और सचिन खंडेलवाल (सीईओ

छात्रों और अधिकारियों ने किया स्वागत

प्रो. ओना लाडवाल (विभागाध्यक्ष, डीएमएस-एसकेआईटी) ने सभी छात्रों और अतिथियों का स्वागत करते हुए एस.के.आई.टी. के प्रबंधन अध्ययन विभाग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद प्रो. डॉ. एस.एल. सुराणा ने छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए प्रबंधन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

और संस्थापक, स्पाइडरलिक ग्रुप) शामिल थे, जिन्होंने अपने व्यावसायिक अनुभव साझा करते हुए छात्रों को प्रबंधन क्षेत्र में आने वाले बदलावों और संभावनाओं के बारे में जानकारी दी

NPS वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ



बेधड़क | जयपुर

जयपुर। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। जयपुर में आयोजित एनपीएस वात्सल्य योजना का कार्यक्रम बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आरआईसी में आयोजित

किया गया। बैंक के संयोजन में कार्यरत एसएलसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने शिरकत की। लगभग 50 लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें कार्ड प्रदान किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक हर्षदकुमार सोलंकी ने सभी का स्वागत किया।



जाहिर खान
स्वतंत्र टिप्पणीकार

बाबा कारंत: दक्षिण और उत्तर रंगमंच को जोड़ने वाले सेतु

19 सितंबर नाटककार बी.वी. कारंत का जन्मदिवस

“ बाबा कारंत को रंगमंच में प्रयोगों से कोई गुरेज नहीं था। नाटकों में अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से उन्होंने नये-नये प्रयोग किए, जो दर्शकों को बेहद पसंद आए। 'छतरियां' जैसे नाटकों में उनके प्रयोग काफ़ी पसंद किए गए। उनके कार्यकाल में भारत भवन का रंगमंडल नई ऊंचाइयों और उत्कर्ष तक पहुंचा। भोपाल के रंगमंडल में बदलाव हुआ। ”

भा रतीय रंगमंच में ब.व. कारंत की पहचान असाधारण रंगकर्मी और रंगमंच प्रशिक्षण देने वाले विद्वान अस्थापक की है। उन्हें लोग प्यार से बाबा कारंत नाम से पुकारते थे। रंग शिबिरों के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ देश भर में सैकड़ों विद्यार्थियों को रंगमंच का प्रशिक्षण दिया, बल्कि उनके निर्देशन में 'सरदार पटेल विद्यालय' दिल्ली, 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' नई दिल्ली, 'भारत भवन रंगमंडल' भोपाल, 'रंगायन' मैसूर और 'बेनका' बंगलूर जैसे नाट्य विद्यालयों और संस्थाओं का विकास हुआ। इनकी देश भर में एक अलग पहचान बनी। हिंदी रंगमंच को ब.व. कारंत ने अपनी नवोन्मेषी दृष्टि से एक नया चरित्र प्रदान किया। वह एक बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार और फ़िल्मकार थे। रंगमंच की सभी

विधाओं में उनकी समान पकड़ थी। ब.व. कारंत की मातृभाषा कन्नड़ थी, मगर उन्होंने हिंदी को इस तरह अपनाया कि उनकी पहचान, हिंदी रंगकर्मी की ही होकर रह गई। जबकि उन्होंने कन्नड़ नाटकों का निर्देशन और कन्नड़ फ़िल्में भी कीं। उनमें अभिनय और संगीत निर्देशन दिया। सच बात तो यह है कि ब.व. कारंत का हिंदी और कन्नड़ दोनों ही जवानों पर समान अधिकार था। यही वजह है कि उन्होंने दक्षिण और उत्तर रंगमंच को जोड़ने में एक सेतु की भूमिका निभाई। और रंगमंच की दुनिया उन्हें इसी रूप में याद करती है। कारंत को भारतीय परंपरा और लोक की गहरी समझ थी। साथ ही आधुनिकता को भी वे साथ लेकर चलते थे। उन्हें नाटकों के वास्तुरूप और नाट्य शिल्प की अच्छी जानकारी थी।

जाहिर है कि जिस शब्द में इतनी सारी खूबियां एक साथ हों, वह कमाल ही होगा। ब.व.कारंत ने न सिर्फ कालिदास के क्लैसिकी नाट्य कृतियों का मंचन किया, बल्कि जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक 'स्कंदगुप्त' और 'चंद्रगुप्त' का भी मंचन किया। उस जमाने में प्रसाद जैसे जटिल नाटककार के नाटक का मंचन करना वाकई एक बड़ी परिघटना थी। बाबूकोडी वेंकटरमण कारंत

यानी ब.व. कारंत की आला तालीम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। जहां उन्होंने हिंदी में एमए करने के बाद पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी के अंडर में पीएचडी की। ब.व.कारंत को क्लासिकल म्यूजिक से भी गहरा लगाव था। यही सबब था कि उन्होंने पं.अंकारनाथ ठाकुर से तीन साल तक भारतीय शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया। आगे चलकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के विद्यार्थी रहे। नाट्यकला में उन्होंने बाकायदा डिप्लोमा किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, बाबा कारंत ने बैंगलूर में 'बैंगलूर कला विद' यानी बेनेका ग्रुप की स्थापना की। बहरहाल,

इसी ग्रुप से उन्होंने अपने प्रयोगधर्मी नाटकों का आगाज किया। 'सतावनानेरु', 'जोगकुमार स्वामी', 'तिंगरकुडणम' आदि नाटकों का निर्देशन किया। ब.व. कारंत बीसवीं सदी के आठवें दशक में मध्य प्रदेश पहुंचे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब 'भारत भवन' रंगमंडल की स्थापना हुई, तो उन्हें इसके निर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। और उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यहां उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण को एक नई दिशा प्रदान की। बाबा कारंत को रंगमंच में प्रयोगों से कोई गुरेज नहीं था। नाटकों में अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से उन्होंने नये-नये प्रयोग किए, जो दर्शकों को

बेहद पसंद आए। 'छतरियां' जैसे नाटकों में उनके प्रयोग काफ़ी पसंद किए गए। उनके कार्यकाल में भारत भवन का रंगमंडल नई ऊंचाइयों और उत्कर्ष तक पहुंचा। भोपाल के रंगमंडल में बदलाव हुआ। नाटक प्रोफेशनल तरीके से तैयार और प्रस्तुत किए जाने लगे। बाबा कारंत ने भोपाल रंगमंडल के लिए जयशंकर प्रसाद- 'विसाख', 'स्कन्दगुप्त', 'शुद्धक-चतुर्भागी', 'गारा की गाड़ी', गिरीश कर्नाड- 'हयवदन', 'प्रेमचंद-कर्मभूमि', 'विजय तेंदुलकर-घासीराम कोतवाल', 'मणिमचुक-रस गंधर्व', डॉ. शंकर शेष- 'एक और द्रोणाचार्य', 'कुमार स्वामिनी' और शेक्सपियर के नाटक 'किंग लियर', 'राजा पगला', 'तीन बेटियों' का निर्देशन एवं मंचन किया।

ब.व. कारंत ने अपने कई नाटक यक्षगान शैली में किए। जिन्हें हिंदीभाषी दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया। उन्हें रंग संस्कार दिए। ब.व. कारंत बहु-आयामी रंग शिल्पियत थे। रंगमंच और नाटक के हर पहलू पर उनकी शानदार पकड़ थी। खास तौर पर नाट्य संगीत की। कारंत ने अपने नाटकों में संगीत का बेहतर इस्तेमाल किया। उनके नाटकों में संगीत कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों की व्याख्या करने का काम करता

है। संवादों को सम्प्रेषणीयता प्रदान करता है। उनके ज्यादातर नाटक सांगीतिक नाटक हैं। कालिदास के क्लासिक नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्', गिरीश कर्नाड- 'हयवदन', विजय तेंदुलकर- 'घासीराम कोतवाल', मणिमचुक- 'रस गंधर्व', 'बगरो बसंत है', 'दो कश्तियों का सवार' और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में उन्होंने संगीत का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया। संस्कृत और कन्नड़ के कई बड़े नाटक मसलन 'स्वप्नवासवदत्ता', 'मूच्छकटिक', 'तुलुक', 'हयवदन', 'हित्तिना हुंजा' और 'केलू जनमेजय' उन्हें के शानदार अनुवाद की वजह से हिंदी में संभव हुए। देश के कई मशहूर किरां और ऐतिहासिक स्थलों 'सबरमती आश्रम', 'गवालियर का किला', 'गोलकुंडा का किला', 'आगरा का लाल किला', 'शनिवार बाड़ा' गुणों में जो लाइट एंड साउंड शो चलते हैं, उनमें भी ब.व. कारंत का म्यूजिक और डायरेक्शन है। ब.व. कारंत वाकई बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार-लेखक-निर्देशक-संगीतकार और विद्वान अस्थापक थे। उन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में जो भी काम किया, उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ी। यही वजह है कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

मीडिया के जरिए सामने आए तथ्यों पर गौर कर जनता करती है फैसला

मजबूत प्रजातंत्र में पत्रकार की भूमिका!



राजीव जैन
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आ जाद भारत के इतिहास में प्रजातंत्र की मजबूती में पत्रकारिता का अहम योगदान रहा है। देश के विकास को मजबूती देने में संसदीय प्रणाली कारगर साबित हुई है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों को जागरूक कर उन्हें सही फैसला लेने का पाठ देश की पत्रकारिता ने ही निभाया है। आजादी के आंदोलन में जिस तरह की भूमिका पत्रकारों की रही उसी तरह का योगदान देश की लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ाने में रही। संसदीय लोकतंत्र में पत्रकार भी जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रजातंत्र को मजबूत करने में किसी से कम नहीं रहे। प्रजातंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता बहुत जरूरी है। इसके लिए पत्रकारिता को स्वयं ही रास्ता चुनकर देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए समय समय पर सुधार के कदम उठाने होंगे।



देश की नीति निर्माता भी समय समय पर पूरी प्रणाली में आवश्यक सुधार की तरफ प्रयास करते हैं। मीडिया भी जहां कहीं भी कमी दिखती है उसे उजागर करने में कोई चूक नहीं करता है। देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से जम गई हैं, इसी का नतीजा है कि कभी भी राजनीतिक अस्थिरता के हालात नहीं बनें। आजादी के बाद सिर्फ आपातकाल के कालखंड में ही अलोकतांत्रिक हालात देखने को मिले।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने एक सम्प्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखने का संकल्प लिया है। इसके लिए ही पत्रकारिता को मजबूती से निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़कर काम करना होगा। देश स्वस्थ प्रजातंत्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाए, इसके लिए नागरिकों को सजग और सचेत करने की दिशा में पत्रकारिता की अहम भूमिका है। संसदीय प्रणाली में ब्यक्त मताधिकार के जरिए जनप्रतिनिधि चुनने का मतलब ही यही है कि जनप्रतिनिधि स्वयं या अपने दल के माध्यम से लोकतंत्र में योगदान देगा। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। चुनावी लोकतंत्र में समय समय पर कई विकृतियां भी सामने आने लगी हैं। इनकी तरफ हमेशा से ही मीडिया ध्यान आकर्षित करती रही है और लोगों में जागरूकता पनपाने की दिशा में काम किया है। इसका ब्यापक असर भी कई बार देखने को मिला है। प्रजातंत्र को असल मायनों में जनता के हितों को बनाने की दिशा में जिस एक सम्प्रभु की तरफ आशाभरी निगाहों से देखा जाता है वो पत्रकारिता ही है। देश के आजादी के आंदोलन में जिन पत्रकारों ने बड़-चढ़कर

हिस्सा लिया था, उन्होंने ही देश में लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने का काम किया। देश में आज निचले स्तर तक लोकतंत्र की मजबूत सीढ़ी कायम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरों नगरीय निकाय भी लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालयों में भी छात्र संघों के निर्वाचन के जरिए युवाओं को प्रजातंत्र की शिक्षा देने का काम हो रहा है। दुनिया के अन्य देशों से तुलना करने पर साफ हो जाता है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। देश के नीति निर्माता भी समय-समय पर पूरी प्रणाली में आवश्यक सुधार की तरफ प्रयास करते हैं। मीडिया भी जहां कहीं भी कमी दिखती है उसे उजागर करने में कोई चूक नहीं करता है। देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से जम गई हैं, इसी का नतीजा है कि कभी भी राजनीतिक अस्थिरता के हालात नहीं बनें। आजादी के बाद सिर्फ आपातकाल के कालखंड में ही अलोकतांत्रिक हालात देखने को मिले। इस दौरान भी मीडिया लोगों को जागरूक करने का काम करता रहा। आपात काल के बाद

सत्ता में हुए बदलाव ने फिर साबित कर दिया कि देश में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी मजबूत हो गई हैं। संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विगत तीस वर्षों में कई बार सत्ता में बदलाव करके जनता ने जता दिया कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता। संसदीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यही है कि हर पांच साल के बाद निर्वाचन का काम होता है। सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल अपने पांच साल का हिसाब किताब जनता के सामने रखता है।

समीक्षा करने के काम को नजरअंदाज कर देगा तो फिर प्रजातंत्र को हानि होना तय है। इसलिए पत्रकारिता को हमेशा सजग और निष्पक्ष तौर पर आकलन करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। पिछले कुछ समय में मीडिया के एक वर्ग पर भी अंगुली उठने लगी है। इससे पत्रकारिता को बचना होगा। पत्रकार अपने काम के प्रति निष्पक्ष और सजग रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र ही मजबूत होगा। पक्ष रहित पत्रकारिता की सोच को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों को भी उस दिशा में काम करना होगा। देश में अब कई विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम चलते हैं। इनके जरिए उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर पत्रकार देश को मिलेंगे और प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। देश के प्रजातंत्र के मजबूत रहने से ही भारत की संघीय व्यवस्था भी ताकतवर रहेगी। संघीय व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारिता एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस प्रणाली से ही हमारे देश की शासन व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों के कल्याण के लिए कारण काम हो सकेगा। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यंग्य

चप्पल और पुल कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं!

भय्या पिछली बार चप्पल बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली। अरे बहन जी आप उस सौ रुपए की चप्पल को 8-10 माह पहले ले गई थी। हा तो क्या इतनी जल्दी टूटती है। इस बार जरा अच्छी, मजबूत, टिकाऊ चप्पल दिखा ना। जो सालों साल चले हों और सस्ती भी हों, सुंदर भी हों। यह सुनकर दुकानदार का दिमाग घन चक्कर हो गया, पर वह ठहरा पक्का दुकानदार उसने भी कोई कच्ची गांटियां नहीं खेती थी। चप्पल का बॉक्स उतारते समय उसकी नजर बीमा पॉलिसी की रसीद पर पड़ी, जिस पर लिखा था "जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी"। उसने मैडम को चप्पल दिखाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम का वही स्लोगन दोहराया और कहा यह चप्पल लीजिए मैडम जो जिंदगी के साथ भी चलेगी और जिंदगी के बाद भी चलेगी। मैडम को दुकानदार की बात जम गई और वही चप्पल पैक करवाली। 150 रुपए की चप्पल के मैडम ने मोल भाव कर 100 रुपए ही दिए। रुपए देने के बाद मैडम ने दुकानदार से कहा भय्या इसका बील बनाकर दो। मैडम की बात सुनकर दुकानदार के सर के बाल और भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने चौंकते हुए कहा क्या इसका बील! मैडम ने कहा हा भय्या हा। दुकानदार ने कहा मैडम आपके पति क्या काम करते हैं? दुकानदार के इस सवाल से मैडम हैरत में पड़ गई और पूछा उससे आपको क्या मतलब? दुकानदार ने कहा मैडम आप चिंता न करें, बताइए तो सही। मैडम ने कहा



आशीष सकलेचा
व्यंग्यकार

वो बड़े पुल बनाने, बड़ी- बड़ी मूर्तियां बनाने के ठेके लेते हैं। दुकानदार हंसने लगा तो मैडम जरा नाराज हो गईं। दुकानदार ने कहा मैडम जब उड़ घाटन से पहले ही करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल बह जाते हैं, करोड़ रुपए की मूर्तियां 8-10 माह में ही गिर रही हैं। वे न तो सस्ते हैं न टिकाऊ हैं न मजबूत हैं। उनका न कोई बील न कोई गारंटी और आप मात्र सौ रुपए की चप्पल की गारंटी और बील मांग रही हैं। दुकानदार की यह बात सुनकर सदी के मौसम में मैडम शर्म से पानी - पानी हो गईं। दुकानदार आगे कुछ कहता उससे पहले ही मैडम बिना कुछ कहे ही चप्पल लेकर चली गईं। दुकानदार ने आवाज लगाते हुए कहा मैडम बील तो ले जाओ पक्का बील दूंगा वो भी जीएसीटी वाला। अब आप भी जीएसीटी के साथ और "फैशन के इस दौर में ग्यारटी की इच्छा न रखें।" हां एक बात और साथ ही साथ "भ्रष्टाचार के इस दौर में मजबूत निर्माण के उम्मीद जरा भी न करें।" जब तक रहेगा समीसे में आलू, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार रहेगा चालू"। इसलिए अब अपनी तमाम इच्छाओं व उम्मीदों को खुंदी पर टांग दो और जिंदगी के मजे लो।

पितृतीर्थ: यहां साक्षात श्रीहरि विष्णु पितृदेव के रूप में हैं विराजमान

गया तीर्थ में ही होती है पितरों की मुक्ति

फल्गु नदी के तट पर स्थित गया श्राद्ध की भूमि है। यह वास्तव में गया नामक असुर की देह ही है जहां पिंडदान करने से मातृ और पितृ पक्ष की सात पीढ़ियों का उद्धार होता है। श्राद्ध के मास में धरती के इस अद्वितीय तीर्थस्थल और पवित्र फल्गु के माहात्म्य का वर्णन भी पाठकों को श्राद्ध से भर देगा। सनातन धर्म परंपरा में पुत्र के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं। पहला- जीवित माता-पिता की सेवा; दूसरा- देहांत के उपरांत उनका श्राद्ध; और तीसरा- उनकी मुक्ति के लिए पवित्र तीर्थ में पिंडदान। इन तीनों को पूरा करने वाला ही अपने पुत्रत्व को सार्थक करता है। दिवंगत माता-पिता के प्रति श्राद्धपूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। आज के नॉलेज कॉर्नर में जानते हैं गया के बारे में...

श्राद्ध कर्म का एकमात्र पर्याय

देवभूमि भारत में असंख्य तीर्थ हैं लेकिन बिहार राज्य का फल्गु नदी के तट पर स्थित गया तीर्थ श्राद्ध कर्म का एकमात्र पर्याय है। गया मानो श्राद्ध की ही भूमि है। शेष तीर्थ स्नान, देवदर्शन, विहार, सुख, शांति और मुक्ति के लिए हैं, किंतु पितरों की मुक्ति के लिए केवल और केवल गया ही है। इसकी महिमा का अनुमान मात्र इससे लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्मविलंबी इसका नाम तक लेते समय सादर 'गयाजी' कहते हैं। इसकी महिमा की यह पराकाष्ठा ही है कि श्राद्ध चाहे घर में हो या प्रयाग, काशी,



पुष्कर, नैमिषारण्य या गंगा किनारे ही क्यों न किया जाए, श्राद्ध का आरंभ ही गयाधाम और गया के प्रधान देवता भगवान गदाधर का स्मरण कर किया जाता है। इस विश्वास के साथ कि यह श्राद्ध फलावाप्ति में गया में किए गए श्राद्ध के समतुल्य ही है। वायुपुराण तो यहां तक कहता है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह गमनरूपी प्रत्येक पद पितरों के लिए स्वर्गमन की सीढ़ी बन जाता है। असुर देह पर विष्णु चरण बिहार की राजधानी पटना से 100 किमी दक्षिण की ओर स्थित गया हिंदुओं के साथ बौद्धों की भी पवित्र भूमि है।

गया की महिमा है अपार

पितृतीर्थ गया की कीर्तिकथा श्रीमद्देवीभागवत, वायुपुराण, कूर्मपुराण, अग्निपुराण, गरुडपुराण से लेकर महाभारत तक सादर गाई गई है। शास्त्रों के अनुसार यह तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वायुपुराण कहता है कि श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाते लगते हैं। कूर्मपुराण के ऋषि सस्वर उद्घोष करते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे माता-पिता दोनों के कुल की सात पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। गया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर अग्निपुराण इस रूप में देता है कि गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान हैं। उन भगवान कमलमयन के दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है।

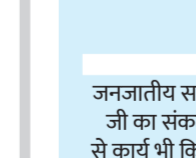
देवी सीता के श्राप का फल

किंवदंती है कि देवी सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी का जल बजाय कलकल नाद के प्रत्यक्ष प्रवाहित होने के, धरती के नीचे अप्रत्यक्ष रूप से बहता है, लेकिन इसके इसी अद्भुत रूप में श्राद्ध का प्रतीक निहित है। मानो यह दिव्य निरंजना निरंजन पितरों तक श्राद्धालुओं की श्राद्ध को अपनी अलौकिक धाराओं के द्वारा पहुंचाती है। **कटेट: प्रताप सिंह नेगी**



नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
@narendramodi

अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को स्वीकृति दी है। इससे ना केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।



अमित शाह, गृह मंत्री
@AmitShah

जनजातीय समाज का सशक्तिकरण मोदी जी का संकल्प है और इस दिशा में तेजी से कार्य भी किया जा रहा है। आज केन्द्रीय कैबिनेट ने 63,000 जनजातीय गाँवों में मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ₹ 79,156 करोड़ की लागत से 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' को मंजूरी दी। इस योजना से 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।



योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
@myogiadityanath

डबल इंजन की सरकार 'डबल स्पीड' के साथ जन-जन के विकास, सम्मान व सुरक्षा तथा युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।



J&K : मतदान के लिए लगी कतार

कश्मीरी विस्थापितों ने दिल्ली में किया मतदान



नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में विस्थापित कश्मीरियों के वोटिंग के लिए दिल्ली में भी चार मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें जम्मू-कश्मीर हाउस, दिलशाद गार्डन, नजफगढ़ और शालीमार बाग शामिल हैं। यहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित बह-चढ़कर मतदान किया। सभी मतदान केंद्रों पर जम्मू कश्मीर आमंड पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। वोटर्स और चुनाव कर्मचारियों के आलावा किसी को भी मतदान केंद्रों तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी।

J&K: घर-घर जनसंपर्क में जुटे सपा प्रत्याशी



लखनऊ। लोकसभा चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मुहिम में जुटी समाजवादी पार्टी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि, राष्ट्रीय पार्टी नहीं होने के कारण उसे अपना पारंपरिक चुनाव निशान साइकिल यहाँ नहीं मिल सका है। ऐसे में सपा को यहाँ लैपटॉप चुनाव चिह्न मिला है। प्रत्याशियों को इसी लैपटॉप और अखिलेश यादव के चेहरे पर भरोसा है। सपा ने 20 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। अधिकांश उम्मीदवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीदवार घर-घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि वे समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर चुनाव में पार्टी का चुनाव चिह्न अलग है।

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव: प्रथम चरण में 60.49 प्रतिशत मतदान

मुस्कुराया लोकतंत्र...बुलेट नहीं बैलट की हुई जय-जयकार

एजेंसी। श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत बुधवार को प्रथम चरण में सात जिलों की कुल 24 सीटों पर मतदान हुआ। हर जगह लोकतंत्र मुस्कुराता नजर आया। मतदान के लिए वोटर्स में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। शाम 7.30 बजे मतदान समाप्त तक 60.49 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। पहले दौर में अनंतनाग जिले की सात, पुलवामा की चार, किरतवाड़, कुलगाम और डोडा की तीन-तीन और रामनगर और शोपियां जिले की दो-दो सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्लिजा मुफ्ती समेत 219 प्रत्याशियों का सियासी भाग्य इंबीएम में बंद हो गया। जम्मू-कश्मीर निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी संख्या को देखते हुए उम्मीद जताई कि इस बार रिफॉर्ड तोड़ मतदान हो सकता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।



पीएम मोदी ने की थी मतदान की अपील

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से वोटिंग की अपील की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील करते हुए कहा कि यह विधानसभा चुनाव जन-जन के उत्कर्ष का नया संकेत लेकर आएगा।

विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। किरतवाड़ में सर्वाधिक 77.23 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे कम पुलवामा जिले में 43.87 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई।

किरतवाड़ जिले की इंद्रवल सीट पर 80 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह पहला अवसर है जब केंद्र शासित प्रदेश में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को तथा तीसरे चरण का चुनाव एक अक्टूबर को है। पुलवामा, किरतवाड़ और कुलगाम में मतदाता मतदान के लिए उमड़ पड़े।

जम्मू कश्मीर में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (गठबंधन), पीडीपी के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने जम्मू में जहां सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में प्रमुख स्थानों पर मतदान

अनंतनाग	: 55.96%
डोडा	: 71.34%
किरतवाड़	: 79.39%
कुलगाम	: 62.46%
पुलवामा	: 46.55%
रामनगर	: 70.55%
शोपियां	: 53.64%

कई दिग्गजों का सियासी भाग्य तय

प्रथम चरण में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्लिजा मुफ्ती (श्रीगुफवारा-बिजबेहरा), कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर (दूरु), माकपा के वरिष्ठ नेता एमवाई तारिगामी (कुलगाम), पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीरजादा सईद (अनंतनाग) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) की सकीना इट्ट (डीएच पोरा) के सियासी भाग्य का भी फैसला इंबीएम में बंद हो गया।

में कुछ ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है और इसने जम्मू क्षेत्र में ही ज्यादातर चेहरे उतारे हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी दोनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अन्य छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है।

कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी

राहुल को धमकियों के खिलाफ कांग्रेस देशभर में करेगी प्रदर्शन

एजेंसी। नई दिल्ली

कांग्रेस लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिल रही धमकियों से चिंतित है और इस मुद्दे पर दो स्तरों पर लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी धमकियों के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगी और इस तरह की टिप्पणी करने वालों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई भी करेगी।

कांग्रेस का मानना है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से आ रही ऐसी धमकियां विपक्ष के नेता को नुकसान पहुंचाने की योजना का हिस्सा हैं, जो केंद्र सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं।

कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने एक समाचार चैनल से कहा है कि हमने सभी प्रदेश इकाइयों को अगले कुछ दिनों में राहुल गांधी को मिल रही धमकियों के खिलाफ विरोध जताने और लोगों को इस मुद्दे के बारे में बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक न्याय के चौपियन हैं और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हम चुप बैठकर उन्हें इस तरह निशाना बनते नहीं देखेंगे।



महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

इस बीच, बुधवार सितंबर को महिला कांग्रेस की सदस्यों ने देशभर में भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री रवीन्द्र बिट्टू की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली और आंध्र प्रदेश यूनिट ने इस मुद्दे पर विरोध जताया।

अब भाजपा सांसद की अमर्यादित टिप्पणी

दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बोडे ने विवादस्पद बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जुबान दाग दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण के बारे में जो कहा है वह खतरनाक है। विपक्षी दलों ने अनिल बोडे की इस विवादित टिप्पणी की आलोचना की। बोडे ने यह टिप्पणी बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी।

शपथ ग्रहण: राष्ट्रपति को तिथि प्रस्तावित, मंजूरी का इंतजार

आतिशी 21 को ले सकती हैं CM पद की शपथ

एजेंसी। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में नामित सीएम आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एलजी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मुर्मू को भेज दिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह दिल्ली में रैलियों का आयोजन करेगी जिनमें अरविंद केजरीवाल जनता का फीडबैक लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को



उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा दिया था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि, आप विधायक दल की ओर से अभी तक मनोनीत सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई तिथि प्रस्तावित नहीं की गई है।

मिल सकती है Z+ सुरक्षा

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि आतिशी को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में आतिशी के सुरक्षा घेरे पर फैसला लिया जाएगा। मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली के सीएम को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

कैबिनेट पर कयास शुरू

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ नई कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उम्मीद है कि नई कैबिनेट में सभी पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से इसमें दो नए चेहरे भी शामिल होंगे। नई कैबिनेट के खाली पदों पर पार्टी क्षेत्रीय व जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी। इसमें एक अनुसूचित जाति के सदस्य को मौका मिल सकता है। दूसरा पूर्वचल समेत दूसरे किसी क्षेत्र का हो सकता है।

अखिलेश यादव ने साधा एसटीएफ पर निशाना

STF में 90% वालों को 10% तैनाती

एजेंसी। लखनऊ

एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा जिन लोगों की जनसंख्या 90 प्रतिशत है, एसटीएफ में उनकी तैनाती केवल दस प्रतिशत है। जबकि जिनकी संख्या दस प्रतिशत है, उन्हें 90 प्रतिशत तैनाती दी गई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स प्लेटफॉर्म पर, 'सरेआम ठोके फोर्स' में तैनात लोगों का ऑकड़ा बता रहा है कि ये तथ्यांक 'विशेष कार्य बल' कुछ बलशाली कृपा-प्राप्त लोगों का 'व्यक्तिगत बल' बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या में



10 प्रतिशत हैं, उनको 90 प्रतिशत तैनाती और जो जनसंख्या में 90 प्रतिशत हैं, उनको 10 प्रतिशत तैनाती। इसका मतलब, इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है, जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अखिलेश यादव ने यूपी एसटीएफ पर भी जोरदार हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि

यूपी में अब एसटीएफ को 'स्पेशल ठाकुर फोर्स' कहा जाने लगा है। भाजपा ने बेइमानी न कराई होती तो सपा-कांग्रेस गठबंधन यूपी में 50 से ज्यादा सीट जीत लेता। जहां तक राम मंदिर में दर्शन करने की बात है, वहां मंदिर निर्माण पूरा हो जाए तो दर्शन करने देना चाहिए। ये बातें अखिलेश ने दिल्ली में एक टीवी चैनल पर बोली थीं।

हरियाणा: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी

किसानों व आधी आबादी पर नजर... MSP, पेंशन व जाति सर्वे का वादा

एजेंसी। नई दिल्ली/ पंचकुला

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने घोषणापत्र में सात अहम वादों का ऐलान किया है जिन्हें 'गारंटी' का नाम दिया गया है। इसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी और जाति सर्वे कराने का वादा शामिल है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने गारंटी पत्र में तेलंगाना मॉडल को अपनाया है तथा बुजुर्गों और महिलाओं पर जोर देते हुए किसानों को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही पार्टी ने जनकल्याणकारी नीतियों पर भी फोकस किया है जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने,



बुजुर्गों को 6 हजार की पेंशन और दो कमरों के मकान का वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे ने दिल्ली

में पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय

माकन और प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खरेगे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम इन गारंटियों को लागू करेंगे और इसलिए हमने इसे 'सात वादे, पक्के इरादे' नाम दिया है। घोषणापत्र में कांग्रेस ने अपने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को 6 हजार रुपए की मासिक पेंशन देने का वादा किया है। इसके साथ ही सरकार में आने पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का भरोसा दिलाया गया है। पार्टी ने जाति सर्वेक्षण और क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं, आम नागरिकों के

कांग्रेस की गारंटियां

- महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर
- बुजुर्गों और दिव्यांगों को 6 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
- 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
- 100 गज का प्लॉट, साढ़े तीन लाख में 2 कमरों का मकान
- एमएसपी की गारंटी और तत्काल फसल मुआवजा
- जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख
- पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने का वादा

लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख का फ्री इलाज दिया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया कि गरीबों को छत प्राप्त हो सके। इसके लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान दिया जाएगा।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और तत्काल फसल पर मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस के संरक्षक पत्र में जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने की भी घोषणा की गई है।

हरियाणा को फिर से नंबर एक बनाएंगे: उदयभान

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक था। उन्होंने कहा, कांग्रेस फिर से हरियाणा को रोजगार, औद्योगिकरण, कृषि, खेल और कानून व्यवस्था में नंबर एक बनाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में हरियाणा में अपराध की पहचान बन गई है।

जरूरी खबर

म्यांमार से लगी सीमा होगी सील, लगेगी बाड़

नई दिल्ली। हथियारों, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए चिंता का सबब बनी भारत-म्यांमार की 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से कांटों की बाड़ लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सैद्धांतिक रूप से भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ज्ञात रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि सीमा के 30 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने इसे मणिपुर में जातीय हिंसा का मूल कारण बताया था। मोरेह के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और मणिपुर के अन्य इलाकों में सीमा के 21 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।

भिवंडी: गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव



ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान पथरावबाजी हुई जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने बताया कि गणपति विसर्जन के दौरान मंगलवार देर रात इलाके की एक मस्जिद के पास खड़ी गई भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, भीड़ ने एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया।

मथुरा में मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे

मथुरा। आगरा-दिल्ली डाउन रेल रूट पर बुधवार रात आगरा से दिल्ली जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें पांच डिब्बे पलटकर आर रूट पर गिर गए। इससे दोनों ओर का रेल ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गया। एक दर्जन से अधिक ट्रेनों रास्ते में ही रोक दी गई हैं। कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। आगरा की ओर से दिल्ली रूट पर कोयला लदी मालगाड़ी बुधवार रात जा रही थी। अचानक वृंदावन रेलवे स्टेशन से आइए के बीच 7.54 बजे मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। पांच डिब्बे पूरी तरह पलट गए हैं।

तटरक्षक बल का पोत पहुंचा इंडोनेशिया



नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल का गश्ती पोत सुजय बुधवार को सद्भावना यात्रा पर इंडोनेशिया के बाली बंदरगाह पहुंचा। पोत पूर्वी एशिया की तैनाती यात्रा पर है। तीन दिवसीय यात्रा के दौरान जहाज का चालक दल इंडोनेशियाई समकक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेगा। इस दौरान समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पाकिस्तान को पानी के लिए पड़ सकता है तरसना

भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस सिंधु जल संधि की समीक्षा पर जोर

एजेंसी। नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझौते, सिंधु जल संधि, में बदलाव चाहता है। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि सिंधु जल समझौते की समीक्षा किया जाना जरूरी है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार भारत ने पिछले महीने की 30 तारीख को पाकिस्तान को यह नोटिस दिया है। जिसमें संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई है। सिंधु जल संधि



के प्रावधानों के अनुसार संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती

के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू-कश्मीर में लगातार सीमा पर से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी

तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बदलाव के खिलाफ होगा क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पाकिस्तान ने भारत की कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध

किया है। पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल संधि में उनके हितों की अनदेखी की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों को लगता है कि सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

क्या है सिंधु जल समझौता

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत भारत को तीन नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण प्राप्त हुआ।

केरल : मंकीपाँक्स का मामला आया सामने

भल्लपुरम (केरल)। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को बताया कि राज्य के मल्लपुरम जिले में मंकी पाँक्स (एमपाँक्स) के एक मामले की पुष्टि हुई है। जॉर्ज ने यह भी बताया कि जिले में पिछले हफ्ते निपाह वायरस से मरने वाले युवक के संपर्क में आए दस अन्य लोगों के नमूने निगेटिव निकले हैं। कुल 266 लोग मृतक के संपर्क में आए थे। इनमें से उच्च जोखिम श्रेणी के 26 लोगों के नमूनों के परिणाम अभी तक निगेटिव आए हैं। मंत्री ने बताया कि मंकीपाँक्स के लक्षण दिखने के बाद एक 38 वर्षीय व्यक्ति को भर्ती कराया है।

कोलकाता: रेप व हत्या का मामला, अपनी बात पर अड़े डॉक्टर मांगें पूरी होने तक हड़ताल खत्म नहीं

एजेंसी। कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर आंदोलनरत जुनियर डॉक्टरों ने अपनी पांच अहम मांगों के पूरा होने तक हड़ताल खत्म करने से मना कर दिया है। डॉक्टरों ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर बुधवार को ही बैठक की गुंजाइश की है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया जा सके और अस्पतालों में खतरनाक माहौल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो सके। डॉक्टरों ने अपने पत्र में कहा है कि सोमवार को हुई मीटिंग में हमें



यकीन दिलाया गया था कि आपकी अगुवाई में एक खास टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इन मुद्दों को सुलझाएगी और इससे जुड़ी बातों पर हमसे चर्चा की जाएगी। हम आप और टास्क फोर्स के शेष सदस्यों के साथ आज ही बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच, तृणमूल

कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य सरकार ने डॉक्टरों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं और इस सद्भावना के तहत डॉक्टरों को अब हड़ताल खत्म करने पर सोचना चाहिए।

दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, कई घर जले

नवादा (बिहार)। बिहार के नवादा जिले में मुफरसिल थाना क्षेत्र के देदौर के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में पक्षों में मारपीट हुई। फिर दबंगों ने दूसरे पक्ष के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में कई घर जलकर राख हो गए। देर रात तक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में एक बड़े भूखंड पर फिलहाल दलित परिवार रहते हैं। इस जमीन पर कब्जा को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है।

सच बेधड़क EXPLAINER एक देश, एक चुनाव: लंबा है सफर, पर कहीं मुकाम भी होगा हैं कई चुनौतियां ... कई बाधाएं करनी होंगी पार

एजेंसी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव संबंधी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे लागू करने की राह आसान नहीं है और देश को कई चुनौतियों से निपटना होगा। कोविंद कमेटी ने इसे लागू करने के लिए कई संविधान संशोधन की सिफारिश की है, मगर इसमें संशोधन करने के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। भारत जैसे बड़े देश में लोकसभा और विधानसभा के साथ अन्य चुनाव कराने की खातिर चुनाव आयोग को भारी साधनों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लंबी तैयारी करने पड़ेगी। एक मतदाता सूची तैयार करनी होगी। चुनाव आयोग के तैयार होने के बाद ही 2029 तक वन नेशन-वन



क्या है एक देश, एक चुनाव
एक देश एक चुनाव यानी का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। ऐसे समझिए, देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोट सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे।

देश में विधायिका की वर्तमान स्थिति
● लोकसभा की कुल सीटें-543
● सभी राज्यों की कुल विधानसभा सीटें- 4130

2029 तक सदस्य संख्या में हो सकता है बदलाव

चर्चा यह है कि साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग साढ़े सात सौ हो सकती है। हालांकि, लोकसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों पर निर्धारण होता है तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व गिर सकता है, जिस कारण वे विरोध कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या की बढ़ोतरी कम हुई है।

कई चरणों में बढ़ाने होंगे कदम

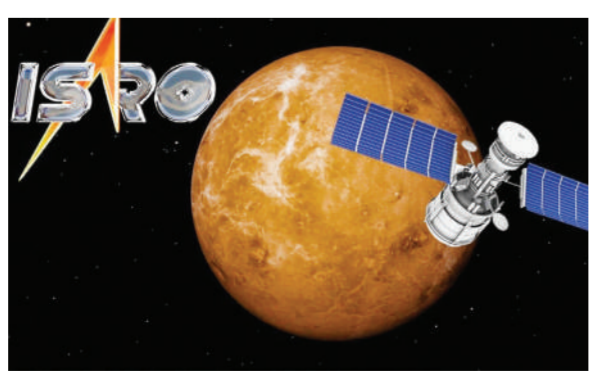
● कोविंद कमेटी के अलावा विधि आयोग भी जल्द ही एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
● विधि आयोग और कोविंद कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी।
● कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की संस्तुति की है। इसके लिए सरकार को संविधान में संबंधित संशोधनों के लिए विधेयक पेश करना होगा। इन संशोधनों को संसद के दोनों सदन में पास होना जरूरी है।
● संसद में विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की शक्ति मिल जाएगी।

एक देश, एक चुनाव के फायदे: ये हैं दावे

चुनाव खर्च में कटौती: देश में बार-बार चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए तक हुआ है, जोकि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। अगर राज्यवार विधानसभा व स्थानीय चुनाव का खर्च भी जोड़ा जाए तो ये खर्च और बढ़ जाएगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर चुनाव खर्च कम होगा।
प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि: चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर पांच साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। देश में बार बार चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षाबलों पर भी दबाव पड़ता है।

चांद तारों से जाना है आगे... अब निगाहें शुक्र ग्रह पर

एजेंसी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अंतरिक्ष मिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुल 31,772 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत चंद्रयान-4 मिशन, गगनयान मिशन के विस्तार और शुक्रयान समेत अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी को दी गई है। इसके अलावा नए रॉकेट सूर्य की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए 2040 का रोडमैप तैयार कर दिया है। नए रॉकेट सूर्य की मंजूरी दी गई है।



कैबिनेट की ये मंजूरी मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के भीतर ही आई है। इसरो के चेयरमैन डॉ. एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष रोडमैप

को अब पंख मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इन चार अहम मंजूरीयों के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और तेजा से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है।

शुक्र ग्रह का होगा अध्ययन

मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 मिशन के अलावा जिस बड़े मिशन को मंजूरी दी है, उनमें शुक्रयान भी बतौर बड़ा मिशन शामिल है। इसके तहत शुक्र ग्रह की सतह, वातावरण, और सौर प्रभावों का अध्ययन करने के लिए शुक्र ऑर्बिटर मिशन (वीओएम) का विकास किया जाएगा। यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए 1,236 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शुक्र ग्रह का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धरती के निकटतम ग्रह है और इसके विकास से यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रहों के वातावरण अलग-अलग तरीके से कैसे विकसित हो सकते हैं।

चांद से नमूने वापस लाएगा चंद्रयान-4

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह से नमूने इकट्ठा कर उन्हें धरती पर वापस लाना है। यह मिशन भारत को भविष्य में चांद पर मानव भेजने और सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी तकनीक को विकसित करने में मदद करेगा। इसमें लैंडिंग, डॉकिंग/अनडॉकिंग, और सुरक्षित वापसी जैसी तकनीकें शामिल हैं। इस मिशन के लिए 2,104 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और इसे 36 महीनों में पूरा किया जाएगा।

अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान की तैयारी

गगनयान मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजने के प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS-1) बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 20,193 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और इसका लक्ष्य दिसंबर 2029 तक पहला यूनिट लॉन्च करना है। इस मिशन के तहत आठ बड़े अभियानों की योजना है, जिसमें अलकंड मिशन भी शामिल है। यह अंतरिक्ष स्टेशन भारत को दीर्घकालिक अंतरिक्ष अनुसंधान में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

हिजबुल्लाह का नामोनिशान मिटाएगा इजराइल!

पेजर अटैक के बाद मिसाइल-तोप से बरसाए बम

एजेसी। तेल अवीव
इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक के बाद तोप और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए।
इसमें मजदल सेलम इलाके में हिजबुल्लाह का एक सैन्य बांचा भी शामिल है, जहां आतंकवादियों को सक्रिय होते हुए देखा गया था। मजदल सेलम इलाके में इजराइली वायु सेना के हमले के अलावा इजराइल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के अन्य पांच क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के बांचों पर हमला किया। यह हमला पेजर अटैक के बाद हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हुए हैं।



इजराइल के कई इलाकों में बजे हवाई सायरन

इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि वायु सेना ने ओडेसेह, मरकाबा, ब्लिंडा, मारून एल रास और चिह्नित क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के बांचों पर भी हमला किया। उत्तरी इजराइल में लेक किन्नरेट के क्षेत्र में कई इलाकों में ड्रोन घुसपैठ अलर्ट जारी किए गए। तिबेरियास, कफर नहूम और गिनोसार सहित अन्य स्थानों पर साइरन बजने लगे। साइरन बजने के बाद, इजराइली मीडिया ने बताया कि तिबेरियास के ऊपर आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम ने दो प्रोजेक्टाइल को मार गिराया, जिसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

इराक से इजराइल पर ड्रोन हमला

इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि गैलिली सागर क्षेत्र में साइरन बजने के बाद एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, जो इराक से इजराइली क्षेत्र में आया था। तिबेरियास में ड्रोन घुसपैठ की आखिरी चेतावनी 11 अक्टूबर, 2023 को दी गई थी। इराक से इजराइल पर ड्रोन हमला मंगलवार को लेबनान में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर विस्फोट में घायल होने के बाद आया है।



हिजबुल्लाह की धमकी-इजराइल को भुगतनी होगी हमले की सजा

हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को इस हमले की सजा जरूर भुगती होगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पेजर में विस्फोटक सामग्री छुपाकर रखी थी। बाद में इन पेजर्स के बम को रिमोट के जरिए एक्टिवेट कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस हमले का बदला इजराइल से जरूर लिया जाएगा।

हिजबुल्लाह की धमकी-इजराइल को भुगतनी होगी हमले की सजा

हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को इस हमले की सजा जरूर भुगती होगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पेजर में विस्फोटक सामग्री छुपाकर रखी थी। बाद में इन पेजर्स के बम को रिमोट के जरिए एक्टिवेट कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस हमले का बदला इजराइल से जरूर लिया जाएगा।

मोसाद ने रची लेबनान में धमाके की साजिश

लेबनान में सिलसिलेवार ढंग से पेजर धमाके धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब लेबनान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले के लिए इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट्स में दावा किया कि मोसाद ने ही हिजबुल्लाह के खरीदे गए पेजर में विस्फोटक लगाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोसाद ने लगभग 5,000 ताइवान-निर्मित पेजर को मॉडिफाई किया था। यह सभी पेजर हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किए थे। इन पेजर में विस्फोटक सामग्री डाली गई थी, जो एक कोड मैसज के जरिए एक्टिवेट की गई। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। धमाका लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में एक-एक कर हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का विदेशी फिल्मों पर अहम फैसला

नेपाल में आस्था को चोट पहुंचाने वाली फिल्मों बैन

एजेसी। काठमांडू
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी सहित सभी विदेशी भाषाओं की ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन पर आगे से रोक लगाने का फैसला किया है, जिसमें नेपाल की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाले दृश्य या संवाद हो। इस संबंध में बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि नेपाल की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति आदि विषय को समेट कर बनाई जाने वाली हिंदी या अन्य विदेशी भाषा की फिल्मों के छायांकन से पहले ही अनुमति नहीं ली जाती है तो ऐसी फिल्मों को नेपाल में चलने पर रोक लगाने का पूरा अधिकार नेपाली सेंसर बोर्ड के पास है।
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनिता सापकोटा की तरफ से दायर रिट पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रकाश ढुंगाना और मनोज शर्मा की संयुक्त बेंच ने कहा है कि सिर्फ धार्मिक आस्था पर आघात पहुंचाने वाली फिल्मों पर ही रोक नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि नेपाल के किसी भी पड़ोसी देश या अन्य मित्र देश के खिलाफ बनाई जाने वाली फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अपने फैसले में जस्टिस ढुंगाना और शर्मा ने लिखा है कि नेपाल के पड़ोसी



आदिपुरुष फिल्म को लेकर नेपाल में हुआ था विवाद

नेपाल में फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर आए फैसले के पूर्ण पाठ में भारत में बनी प्रभास की आदिपुरुष फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने और नेपाल की बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की भी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई है। नेपाल में आदिपुरुष फिल्म के प्रदर्शन के दौरान उसका काफी विरोध हुआ था और इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी। फिल्म के रिलीज के समय भी कई दिनों तक नेपाल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी।

देश या अन्य मित्र राष्ट्र के साथ हमारे संबंध पर ही असर डालने वाली कोई भी फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी नेपाल सेंसर बोर्ड की है।
विदेशी फिल्मों के नेपाल में प्रदर्शन से पहले सेंसर बोर्ड को हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर असर डालने वाली फिल्मों को नेपाल सरकार, विदेश मंत्रालय और

सरकार ने दिए आदेश

देश में भुखमरी, खाने के लिए मारेंगे हाथी

एजेसी। हरारे
अफ्रीका के कई देशों को इन दिनों सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जिम्बाब्वे की बात की जाए तो यहां पर 40 साल में अब तक का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। यही वजह है कि सूखे के कारण फसल नहीं हो रही है। फलस्वरूप वहां के लोगों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। इसको देखते हुए सरकार ने लोगों का पेट भरने के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। ये आदेश विशेष रूप से उन समुदायों के लिए है जो भयानक भूख से जूझ रहे हैं।
जिम्बाब्वे की सरकार ने लोगों का पेट भरने के लिए हाथियों का मांस खिलाने का निर्णय लिया है। इसका खुलासा जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने



जीवों के अस्तित्व पर संकट

सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि भोजन की गंभीर कमी को पूरा किए जाने के साथ ही लोगों का पेट भरा जा सके। हालांकि जानवरों की हत्या को लेकर यह फैसला विवादास्पद है और इससे वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि जीवों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है।
किया है। जिम्बाब्वे में भुखमरी और सूखे के हालात के कारण जानवरों के शिकार में इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हो

नामीबिया में मारे जा चुके हैं कई हाथी

नामीबिया में भी 83 हाथियों को मारने के बाद उनका मांस भूखे इंसानों को खिलाया गया था। जिम्बाब्वे की तरह नामीबिया में भी भुखमरी की समस्या को कम करने की कोशिश की गई थी। अफ्रीका के पांच प्रमुख इलाकों जिम्बाब्वे, जांबिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में दो लाख से ज्यादा हाथी रहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी का हिस्सा है।
वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के प्रवक्ता तिनशे फराबो ने पुष्टि की है कि सरकार ने 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है।

सिटी काउंसिल ने पारित किए दो नए विधेयक

वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं पर लगाम

वाशिंगटन। अमेरिका में सिएटल सिटी काउंसिल ने दो नए विधेयक पारित किए। इनका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से नशीली दवाओं के उपयोग, बिक्री और वेश्यावृत्ति पर लगाम लगाना है। पहले विधेयक में यह प्रावधान है कि अब नशीलों दवाओं के सौदागरो के सिएटल शहर के मुख्य भाग स्टे आउट ऑफ ड्रग एरिया में प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, नशीली दवाओं से



संबंधित विधेयक लाने का प्रस्ताव काउंसिल सदस्य बॉब केटल ने किया। इसे सिटी अर्थोनी एन डेविंसन ने पेश किया। यह विधेयक

ऑरिगा एवेन्यू से संबंधित है। यह जगह वेश्यावृत्ति और आवागमन के लिए बंदनाम है। इसमें कहा गया है कि सेक्स वर्कर को यहां से दूर कर दिया जाएगा। काउंसिल सदस्य कैथी मूर का यह विधेयक भी 8 से 1 के अंतर से पारित हुआ। काउंसिल सदस्य टैमी मोरालेस ने इस विधेयक के खिलाफ भी मतदान किया। उल्लेखनीय है कि सिएटल वाशिंगटन राज्य का एक प्रमुख शहर है।

राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम

वेधड़क अंदाज, वेधड़क खबरें

टीवी न्यूज़ चैनल एवं दैनिक हिन्दी अखबार

Channel Now Available on

TATA PLAY 1186	airtel digital 372	RM Cable 123	Rabunt 345
DCN 987	GTPL 986		

OUR DIGITAL PARTNER

B-37, 38, 39, Kamal Ratan Tower, 10-B Scheme, Gopalpura Bypass Road, Jaipur, 302018

✉ official@sachbedhadak.com 🌐 www.sachbedhadak.com 📞 +91 9664014179

Sach Bedhadak
 Sach Bedhadak
 Sach Bedhadak
 sach_bedhadak

दैनिक हिन्दी अखबार

सच बेधड़क

“सच बेधड़क” दैनिक हिन्दी अखबार की प्रति PDF के माध्यम से मुफ्त प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए



Telegram

<https://rb.gy/3bkrnl>

